बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 207 ● नई दिल्ली ● बुधवार 03 जून 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

दिल्ली रिज की सुरक्षा के लिए रिज मैनेजमेंट बोर्ड का पुनर्गठन, एलजी का हरित विरासत और पर्यावरणीय संतुलन पर जोर

नई दिल्ली। राजधानी की हरित विरासत और पर्यावरणीय संतुलन को मजबूत करने के उद्देश्य से उपराज्यपाल टीएस संधू ने दिल्ली रिज मैनेजमेंट बोर्ड (डीआरएमबी) के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप गठित इस नए बोर्ड का उद्देश्य दिल्ली रिज क्षेत्र की सुरक्षा, संरक्षण और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करना है। पुनर्गठित बोर्ड की अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे, जबकि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के उपाध्यक्ष सदस्य होंगे। इसके अलावा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, एमसीडी, एनडीएमसी, दिल्ली पुलिस, सीपीडब्ल्यूडी, राजस्व विभाग और पर्यावरण एवं वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी बोर्ड में शामिल किए गए हैं।

दिल्ली में जल्द शुरू होगा ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन, समय पर होंगे काम; बुराड़ी आरटीओ पहुंचीं सीएम रेखा गुप्ता

नई दिल्ली।

दिल्ली सरकार ने नागरिकों को बेहतर और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक और कदम उठाते हुए बुराड़ी स्थित परिवहन विभाग की विभिन्न इकाइयों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने डीटीओ , व्हीकल इंस्पेक्शन यूनिट, व्हीकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन का दौरा कर वहां उपलब्ध सुविधाओं और कार्यों की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं, सेवा वितरण व्यवस्था और कार्यालयों में कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई।

अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि आम लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और सेवाओं को अधिक सरल, पारदर्शी तथा समयबद्ध बनाया जाए। इस दौरान ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन के निर्माण कार्यों की भी विस्तृत समीक्षा की गई। संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि निर्माण कार्य निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा किया जाए, ताकि नागरिकों को आधुनिक और तकनीक आधारित वाहन परीक्षण सुविधाएं जल्द उपलब्ध कराई जा सकें। निरीक्षण के बाद कहा गया कि दिल्लीवासी सरकारी दफ्तरों में अपनी समस्याओं के समाधान और जरूरी सेवाओं के लिए आते हैं। ऐसे में यह सरकार की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक सेवा सुगम, पारदर्शी और तय समय के भीतर उपलब्ध कराई जाए। सरकार ने दोहराया कि नागरिक सुविधाओं से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की कमी मिलने पर तत्काल सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। साथ ही जहां लापरवाही या अनियमितता सामने आएगी, वहां संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी। सरकार का कहना है कि प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक जवाबदेह और नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए ऐसे औचक निरीक्षण लगातार जारी रहेंगे, जिससे सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित किया जा सके।

ओएसएम पोर्टल पर सवाल उठाने वाला छात्र पहुंचा संसद, समिति के सामने रखीं सिस्टम की खामियां

नई दिल्ली।

सीबीएसई की ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को लेकर उठे विवाद ने अब नया मोड़ ले लिया है। कक्षा 12वीं के छात्र सार्थक सिद्धांत ने मंगलवार को संसद की शिक्षा, महिला, बाल, युवा एवं खेल संबंधी स्थायी समिति के सामने पेश होकर ओएसएम सिस्टम और उससे जुड़े टेंडर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं पर अपनी प्रस्तुति दी। संसद भवन एनेक्सी में आयोजित बैठक में समिति सीबीएसई की कक्षा 12 बोर्ड परीक्षाओं में लागू ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रणाली और छात्रों द्वारा उठाई गई पारदर्शिता व मूल्यांकन संबंधी चिंताओं की समीक्षा कर रही है। बैठक से पहले सार्थक सिद्धांत ने दावा किया कि सीबीएसई के विभिन्न टेंडर दस्तावेजों की तुलना करने पर कई विसंगतियां सामने आई हैं। उनके अनुसार इन बदलावों से एक विशेष सेवा प्रदाता को फायदा पहुंचाने की आशंका दिखाई देती है। सार्थक ने कहा कि उन्होंने अपने ब्लॉग में कम से कम 15 विसंगतियों का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि समिति के सामने वे इनमें से तीन से चार प्रमुख मुद्दों को विस्तार से रखेंगे। छात्र ने आरोप लगाया कि ओएसएम प्रणाली से जुड़े नए टेंडर दस्तावेजों में कई महत्वपूर्ण शर्तों को बदल दिया गया। उनके मुताबिक पुराने टेंडर में खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों को अयोग्य घोषित करने से संबंधित तीन महत्वपूर्ण शर्तें थीं, लेकिन नए आरएफपी में इन प्रावधानों को पूरी तरह हटा दिया गया। सार्थक ने यह भी दावा किया कि ब्लैकलिस्टिंग, वित्तीय पात्रता सीमा, CMMI स्तर और प्रोजेक्ट पात्रता से जुड़े नियमों में भी बदलाव किए गए। सार्थक सिद्धांत ने बताया कि इस मामले पर उनका अध्ययन एथिकल हैकर निसर्ग अधिकारी और इस विषय की जांच कर रहे कुछ पत्रकारों के सहयोग से किया गया। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस पूरे मुद्दे से सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया और शिक्षा मूल्यांकन प्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाने की दिशा में चर्चा आगे बढ़ेगी। सार्थक ने साफ किया कि वे ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के पूरी तरह खिलाफ नहीं हैं।

उनका कहना है कि यह एक अच्छा बदलाव हो सकता है, लेकिन इसे लागू करने से पहले बड़े स्तर पर परीक्षण और डेमो पायलट किए जाने चाहिए थे। उन्होंने कहा, ओएसएम एक अच्छा बदलाव है, लेकिन इसे लागू करने से पहले व्यापक स्तर पर ट्रायल और पायलट प्रोजेक्ट होने चाहिए थे। सूत्रों के अनुसार संसदीय समिति कक्षा 9वीं और 10वीं में लागू तीन-भाषा फॉर्मूला की समीक्षा भी कर रही है। समिति शिक्षा व्यवस्था से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर फीडबैक और सुझाव एकत्र कर रही है। सीबीएसई की ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को लेकर बढ़ती बहस के बीच अब सभी की नजर संसदीय समिति की आगामी सिफारिशों पर टिकी हुई है।

दिल्ली सचिवालय में सीएम रेखा गुप्ता और जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई बड़ी बैठक, इन मुद्दों पर हुई चर्चा

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में जर्मनी के थुरिंगिया राय के मंत्री-प्रमुख मारियो वोग्ट और एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की। इस चर्चा का मुख्य फोकस शहरी विकास, टेक्नोलॉजी, शासन और कौशल विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाना था। बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने स्मार्ट शहरी विकास, टिकाऊ बुनियादी ढांचे, डिजिटल शासन और इनोवेशन-आधारित सार्वजनिक सेवाओं में सहयोग के अवसरों पर विचार-विमर्श किया। चर्चा में मोबिलिटी समाधान, जल प्रबंधन, पर्यावरण टेक्नोलॉजी, शिक्षा और कौशल विकास की पहलें भी शामिल थीं, जिनका उद्देश्य भारत और जर्मनी के बीच प्रतिभाओं के आदान-प्रदान को मजबूत करना है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत और जर्मनी के संबंध कई क्षेत्रों में लगातार गहरे होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली इनोवेशन, स्थिरता-केंद्रित परियोजनाओं और मानव संसाधन विकास की पहलों के माध्यम से इस बढ़ती साझेदारी में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 𝕏 पर बैठक का विवरण साझा करते हुए कहा कि जर्मनी के थुरिंगिया राज्य के मंत्री-प्रमुख श्री मारियो वोग्ट और उनके साथ आए प्रतिनिधिमंडल के साथ मेरी बातचीत बहुत सार्थक रही। हमने इन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की स्मार्ट शहरी विकास और टिकाऊ बुनियादी ढांचा, डिजिटल शासन और इनोवेशन, कौशल विकास और प्रतिभाओं का आदान-प्रदान; मोबिलिटी, जल प्रबंधन और पर्यावरण टेक्नोलॉजी; तथा शिक्षा और कार्यबल विकास। माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में, भारत और जर्मनी की साझेदारी विभिन्न क्षेत्रों में लगातार मजबूत हो रही है। दिल्ली को इनोवेशन, स्थिरता और मानव विकास की इस साझा यात्रा में योगदान देने पर गर्व है।+ आए हुए प्रतिनिधिमंडल और दिल्ली सरकार के प्रतिनिधियों ने उन क्षेत्रों की भी समीक्षा की, जहाँ शहरी नियोजन, स्वच्छ ऊर्जा बदलाव और नगरपालिका शासन में जर्मनी की विशेषज्ञता दिल्ली की चल रही विकास प्राथमिकताओं को पूरा करने में सहायक हो सकती है।

अधिकारियों ने बताया कि यह बातचीत राय स्तर पर अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों को बढ़ाने के व्यापक प्रयासों का एक हिस्सा है। यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब भारतीय राज्यों और वैश्विक साझेदारों के बीच जलवायु लचीलापन, स्मार्ट सिटी नियोजन और डिजिटल बदलाव जैसे मुद्दों पर आपसी जुड़ाव बढ़ रहा है। दिल्ली नागरिक बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने, सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी को मजबूत करने और टिकाऊ शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक स्तर की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को अपनाने का प्रयास कर रही है।

दिल्ली के साई हत्याकांड में स्वजनों ने छतरपुर लालबत्ती पर शव रख किया प्रदर्शन, बोले- आरोपितों को मिले फांसी

नई दिल्ली। दक्षिण-पूर्वी जिला के अमर कॉलोनी में 26 मई को गोलिकांड में घायल साई कुमार की मौत के दूसरे दिन मंगलवार को शव पहुंचाया गया। परिवार आरोपितों के एनकाउंटर की मांग कर रहा है। क्राइम ब्रांच अब तक नाबालिग मुख्य आरोपित समेत तीन को पकड़ चुकी है। वहीं, एक नाबालिग अभी भी है फरार। वारदात से नाराज स्वजनों व स्थानीय लोगों ने छतरपुर लालबत्ती पर युवक का शव रखकर ने प्रदर्शन किया। वे आरोपितों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने बहुत समझाने का प्रयास किया। हालांकि, वे अपनी मांग पर अड़े रहे। इस बीच सड़क पर काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही। बता दें कि दक्षिण-पूर्वी जिला के अमर कॉलोनी इलाके के एक रेस्तरां में युवती को घूरने का विरोध करने पर 17 साल किशोर के सिर में गोली मारने के मामले को पुलिस आयुक्त ने जिला पुलिस से हटाकर क्राइम ब्रांच को सौंप दी था। इसके साथ ही, पुलिस इस मामले में पकड़े गए मुख्य आरोपित 16 साल के किशोर के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में एक याचिका दायर करने पर विचार कर रही है, ताकि अपराध की गंभीरता और उसके आपराधिक इतिहास को देखते हुए उस पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जा सके। पुलिस अधिकारी के मुताबिक, वारदात में मुख्य आरोपित ओखला के श्याम नगर का रहने वाला 16 साल का किशोर है। पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपित समेत तीन अन्य उसके साथ थे। फिलहाल, इनमें से एक नाबालिग फरार चल रहा है। इस संबंध में किशोरी ने पुलिस को बताया था कि वह अपने दोस्त के साथ रेस्तरां में बैठी थी। तभी वहां मौजूद लड़कों में से एक ने उसकी बगल वाली कुर्सी के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी और घूरना शुरू कर दिया। जब साई ने इस पर आपत्ति जताई, तो वह लड़का साई को घूरने लगा और उसके साथ गाली-गलौज करने लगा। साई ने किशोरी से कहा कि वह जल्दी से खाना खत्म कर वहां से निकल जाए। इस बीच आरोपित भी कुछ देर के लिए वहां से चले गए लेकिन थोड़ी ही देर बाद वे वापस लौट आए। युवती के अनुसार, जिस लड़के ने साई को गाली दी थी, उसने साई के सिर के पीछे गोली मार दी। वारदात के बाद वहां मौजूद लोगों ने जब उन लोगों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे हवा में हथियार लहराते हुए फरार हो गए।

सीजेआई सूर्यकांत ने 5 नए न्यायाधीशों को दिलाई शपथ, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों संख्या बढ़कर 37 हुई

नई दिल्ली। भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने उच्चतम न्यायालय के पांच नए न्यायाधीशों को मंगलवार को पद की शपथ दिलाई और इसके साथ ही शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 37 हो गई जो अब तक की सर्वाधिक संख्या है। प्रधान न्यायाधीश ने वरिष्ठ अधिवक्ता वी. मोहना, न्यायमूर्ति शील नागू, न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह उच्चतम न्यायालय परिसर में आयोजित किया गया। शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या अब 37 हो गई है जो बढ़ाई गई स्वीकृत संख्या 38 से एक कम है।

केंद्र ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नागू, बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सचदेवा, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पल्ली तथा वरिष्ठ अधिवक्ता मोहना को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए जाने को सोमवार को मंजूरी दी थी। सरकार ने पिछले महीने एक कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी किया था जिसके तहत भारत के प्रधान न्यायाधीश सहित उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 कर दी गई।

कॉलेजियम ने इन पांच नए नामों की थी सिफारिश

उच्चतम न्यायालय के दो मौजूदा न्यायाधीश- न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति जे. के. माहेश्वरी- क्रमश 16 जून और 28 जून को सेवानिवृत्त होंगे। उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने 27 मई को इन पांच नए नामों की सिफारिश की थी और चार दिन में ही इनकी नियुक्तियों को मंजूरी मिल गई। न्यायमूर्ति मोहना 2018 में न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा के बाद बार से सीधे उच्चतम न्यायालय में नियुक्त होने वाली देश की दूसरी महिला बन गई हैं। वह उच्चतम न्यायालय में सेवारत दो महिला न्यायाधीशों में से एक होंगी। उनके अलावा एक अन्य महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना हैं जो 31 अगस्त, 2021 से शीर्ष अदालत की न्यायाधीश हैं।

न्यायमूर्ति नागरत्ना के 2027 में बन सकती है प्रधान न्यायाधीश

न्यायमूर्ति नागरत्ना के 2027 में एक महीने से अधिक समय के लिए प्रधान न्यायाधीश बनने की भी संभावना है। एक जनवरी, 1965 को जन्मे न्यायमूर्ति नागू अक्टूबर 1987 में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत हुए थे। उन्हें 27 मई, 2011 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया और 23 मई, 2013 को वहां स्थायी न्यायाधीश बनाया गया। न्यायमूर्ति नागू को 25 मई, 2024 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। उन्होंने नौ जुलाई, 2024 को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। वह उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त उस आंतरिक समिति का हिस्सा थे, जिसने पिछले साल मार्च में दिल्ली उच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास पर जली हुई नकदी मिलने के आरोपों की जांच की थी। न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर का जन्म 25 मई, 1965 को हुआ था।

दिल्ली उच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता के पद किया काम

दिल्ली उच्च न्यायालय ने जुलाई 2011 में उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता नामित किया। न्यायमूर्ति सचदेवा को 17 अप्रैल, 2013 से दिल्ली उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया और उन्हें 18 मार्च, 2015 को वहां स्थायी न्यायाधीश बनाया गया। उनका 30 मई, 2024 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में तबादला किया गया। न्यायमूर्ति सचदेवा ने 17 जुलाई, 2025 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।

18 सितंबर, 1964 को जन्मे न्यायमूर्ति पल्ली ने 1988 में पंजाब विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की पढ़ाई पूरी की। उन्हें 26 अप्रैल, 2007 को वरिष्ठ अधिवक्ता नामित किया गया। न्यायमूर्ति पल्ली को 28 दिसंबर, 2013 को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की पीठ में पदोन्नत किया गया। उन्हें जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया और उन्होंने 16 अप्रैल, 2025 को वहां पद की शपथ ली। न्यायमूर्ति मोहना (59) ने 1988 में कोयंबटूर लॉ कॉलेज से स्नातक की डिग्री ली और तभी से वह वकालत कर रही हैं।

दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला- प्री-कास्ट तकनीक से बनेंगे नाले, मॉनसून से पहले तैयार होगा ड्रेनेज सिस्टम

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में हर साल मानसून के दौरान होने वाले गंभीर जलभराव से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने तैयारी शुरू की है। लंबे समय के लिए काम आने के लिए नालों का निर्माण काम शुरू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में पिछले वर्ष घोषित किए गए नए ड्रेनेज मास्टर प्लान को अब युद्धस्तर पर जमीन पर उतारने की तैयारी है। इस योजना के तहत नालों के निर्माण और रीमॉडलिंग कार्य में लगने वाले समय को कम करने के लिए सरकार ने आधुनिक प्री-कास्ट तकनीक को अपनाने का फैसला किया है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने राजधानी के विभिन्न चिन्हित और संवेदनशील जलभराव वाले इलाकों के लिए इस तकनीक से नालों के निर्माण हेतु आधिकारिक तौर पर निविदाएं (टेंडर) जारी कर दी हैं। पारंपरिक निर्माण पद्धतियों (कास्ट -इन-सीटू) को पीछे छोड़ते हुए इस आधुनिक तकनीक के तहत नालों के आकार के कंक्रीट बाक्स पहले ही फैक्टरी या यार्ड में तैयार कर लिए जाते हैं।

चंगा सी...

ये जार्ज सोरोस क्या बिल्कुल ही पगला गया है? नहीं तो ये विपक्ष वाले कैसे शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा मांग रहे हैं? और वह भी पेपर लीक जैसी मामूली बात के लिए? नहीं, हम यह नहीं कह रहे हैं कि भारत में विपक्ष वालों को अपने आप से शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने का आइडिया आ ही नहीं सकता था। बेशक, विपक्ष वालों को अपने आप भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने का आइडिया आ सकता था। नीट पेपर लीक जैसी मामूली बात के लिए इस्तीफा मांगने का आइडिया भी आ सकता था। सच पूछिए तो नीट पेपर लीक के लिए इस्तीफा मांगने का आइडिया तो वैसे भी इसलिए भी आ ही सकता था कि नीट पेपर के लीक होने से धर्मेंद्र प्रधान का रिश्ता ठीक-ठाक पुराना है। दो साल पहले भी ऐसे ही नीट का पेपर लीक हुआ था। उस समय भी ऐसे ही हल्ला-गुल्ला हुआ था। उस समय भी सीबीआई समेत कई तरह की जांच हुई थीं। उस समय भी पेपर लीक गिरोह की गिरफ्तारियां हुई थीं। उस समय भी विपक्ष वालों ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की थी। और उस समय भी धर्मेंद्र प्रधान ने सिर्फ इस्तीफा देने से ही नहीं, पेपर लीक के पेपर लीक होने से भी इंकार कर दिया था। अब अगर नीट का पेपर लीक, लीक होने की अपनी आदत छोड़ने से इंकार कर सकता है, अगर विपक्ष मंत्री का इस्तीफा मांगने की अपनी आदत बनाए रख सकता है, तो क्या मोदी जी पेपर लीक के सारे शोर के बाद भी, धर्मेंद्र प्रधान को मंत्री का मंत्री ही नहीं, शिक्षा का शिक्षा मंत्री भी नहीं बनाए रख सकते हैं? बल्कि हम तो कहेंगे बनाए रख सकते हैं का तो सवाल ही गलत है। मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है। पर विपक्ष वालों को भी तो इस्तीफा मांगने से पहले कुछ सोचना चाहिए। मोदी जी को पेपर लीक जैसी मामूली बात के लिए, अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए क्या? अब प्लीज मोदी जी के विरोधियों के साथ खड़े होकर आप यह मत कहने लगिएगा कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा लेने के लिए मोदी जी को बार-बार मौके ही नहीं दिए हैं, कई-कई ऑप्शन भी दिए हैं। नीट पेपर लीक के लिए इस्तीफा लेना पसंद नहीं आए, तो सीबीएसई की 12वीं कक्षा की परीक्षा की कॉपी जांच महा-गड़बड़ी के लिए शिक्षा मंत्री का ही इस्तीफा ले सकते हैं। नीट का मामला अगर 22 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का था, तो सीबीएसई का भी उससे थोड़े ही कम, 18 लाख बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ का था। सीबीएसई के लिए भी इस्तीफा लेने पर मन नहीं ठहरे तो, मोदी जी एसएससी परीक्षा धपले के लिए भी उन्हीं प्रधान का इस्तीफा ले सकते हैं। और वह भी नहीं जंचे तो तानातानी सीयूईटी परीक्षा गड़बड़ी के लिए भी उन्हीं प्रधान का इस्तीफा ले सकते हैं। बेशक, मोदी जी इस्तीफा ले सकते हैं। इनमें से किसी भी मामले में इस्तीफा ले सकते हैं। लेकिन, जैसे एक कारण, वैसे ही चार कारण, मोदी जी इस्तीफा लेने से इंकार भी तो कर सकते हैं। और इंकार भी क्यों करना? मोदी जी इस्तीफे की मांग सुनें ही क्यों? बापू के तीन बंदरों का सन्देश मोदी जी कभी नहीं भूलते! खैर जार्ज सोरोस पर लौटें। देखो विपक्ष वालों को भले ही याद नहीं हो, पर जार्ज सोरोस को बखूबी याद होगा कि मोदी जी के राज और मंत्रियों के इस्तीफे में और वह भी तब जब विपक्ष इस्तीफा मांग रहा हो, कैसा छत्तीस का आंकड़ा है। मोदी जी की तीसरी पारी चल रही है, जबकि राजनाथ सिंह ने उनकी पहली पारी के भी शुरू में ही एलान कर दिया था कि डेमोक्रेसी में विपक्ष, मंत्रियों का इस्तीफा मांगने के लिए आजाद है, पर मोदी जी के राज में इस्तीफे नहीं होते। और विपक्ष के मांगने से इस्तीफे तो होंगे ही नहीं। विपक्ष के मांगने से इस्तीफे पहले वाली कमजोर सरकारों में हुआ करते थे। मोदी जी की मजबूत सरकार और विपक्ष की मांग से इस्तीफा, सवाल ही नहीं उठता है। राजपूती वचन मोदी जी ने डटकर निभाया है, न विपक्ष की मांग पर और न लोक-लाज के डर से, अपनी सरकार से एक भी मंत्री को नहीं हटाया है। जैसे बारह साल में मोदी जी ने देश में तो देश में, परदेस तक में एक भी खुली प्रेस कान्फ्रेंस न करने का धर्म निभाया है, वैसे ही हर दागी मंत्री का साथ निभाया है। सोरोस को मोदी जी का यह प्रण बखूबी याद होगा, फिर भी विपक्षी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं? आखिर क्यों? जाहिर है कि षड्यंत्र है। और वह भी विदेशी; आत्मनिर्भरता का पेटेंट तो मोदी जी के पास है। जार्ज सोरोस का षड्यंत्र बहुत गहरा है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग सिर्फ पेपर लीक वगैरह के लिए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग नहीं है। बात यहां से निकल जरूर रही है, पर दूर तक जाएगी। क्या कल को रुपए से लेकर अर्थव्यवस्था तक, सब के तेजी से लुढ़कने के लिए निर्मला ताई के इस्तीफे की मांग नहीं आएगी? और उससे पहले ही, एप्सटीन मामले से लेकर, तेल-गैस तंगी तक के लिए, तेल मंत्री पुरी साहब के इस्तीफे की मांग। उसी के आस-पास दुनिया भर में भारत का डंका बजवाने की जगह, डंका फटने का ही डंका बजवाने के लिए, लेजर आई वाले विदेश मंत्री के इस्तीफे की मांग। अमरीका के साथ व्यापार सौदे के जरिए, सिर्फ अमरीका को ग्रेट अगेन और भारत को गरीब अगेन बनाने का रास्ता खोलने के लिए, वाणिज्य मंत्री गोयल के इस्तीफे की मांग की मांग। रेल दुर्घटनाओं की आपदा की जगह रील बनाने का अवसर बनाने के लिए, रेल से लेकर सूचना, प्रसारण और आइटी तक के मंत्री, वैष्णव के इस्तीफे की मांग। संसद को सरकारी डिपार्टमेंट बनाकर रख देने के लिए, संसदीय कार्यमंत्री, रिजिजू के इस्तीफे की मांग। सब कुछ असली राष्ट्र सेठ के नाम करने के लिए, उद्योग मंत्री के इस्तीफे की मांग। ऑपरेशन सिंदूर के बाद, पाकिस्तान को और शेर बनाने के लिए, रक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। फलां मंत्री के इस्तीफे की मांग, ढिमकां मंत्री के इस्तीफे की मांग। और आखिर में, जहां-जहां चुनाव हों वहां हिंदुओं को खतरे में पड़वाने के लिए, गृहमंत्री शाह के भी इस्तीफे की मांग। मांग निकलेगी तो छोटा भाई तक ही थोड़े ही रुकेगी, मोटा भाई तक जाएगी, जबकि बाकी सब तो चंगा सी। यही तो है सोरोस का असली षड्यंत्र। इसीलिए, कितनी ही बदनामी हो जाए, मोदी जी किसी मंत्री का इस्तीफा नहीं लेंगे। मोदी जी अपने इस्तीफे की एडीशनल मांग का रास्ता हर्गिज नहीं खोलेंगे? और क्यों खोलें, एक मामूली पेपर लीक के लिए; कुल 50 लाख बच्चों की, उनके परिवारों की परेशानी के लिए ; बाकी सब तो चंगा सी।(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और लोक लहर के संपादक हैं।)

बालेन शाह और नेपाल

जनक्रांतियों के बाद सत्ता हासिल करने की प्रक्रिया को इतिहास में कई अलग-अलग तरीकों से अंजाम दिया गया है। जब कोई क्रांति सफल होती है तो उसके बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुरानी व्यवस्था के ढांचे को भंग कर नई व्यवस्था स्थापित कर स्थिर सरकार प्रदान करना होता है। क्रांति के बाद सत्ता हासिल करना बहुत आसान होता है लेकिन सत्ता को चलाना आसान नहीं होता। अगर सत्ता को ठीक तरह से न संभाला जाए तो अवसर शक्ति के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है तब अराजकता की स्थिति पैदा होने की आशंका बन जाती है। सत्ता और उसकी दिशा का निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि नई राजनीतिक व्यवस्था और नए शासकों का उदय कितना समझदारी से आगे बढ़ता है। शासन को चलाने के लिए बहुत परिपक्वता की जरूरत होती है। क्रांतियों के बाद सत्ता का हस्तांतरण एक जटिल और संवेदनशील प्रक्रिया है। इसलिए नए शासकों को फूंक-फूंक कर कदम रखना होता है। राजतंत्र और तानाशाहों को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतियां होती रही हैं। देखना यह होता है कि क्या क्रांतियों के बाद वहां के लोगों को अपनी इच्छाओं के अनुरूप शासन मिल रहा है या नहीं। किसी भी क्रांति के बाद नई सरकारों को पड़ोसी देशों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कूटनीतिक संबंधों को सुधारने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए आज के दौर में जब दुनियाभर में नए समीकरण बन रहे हों तो संभल कर चलने की जरूरत होती है। पड़ोसी देश नेपाल में जेन जी की क्रांति के बालेन्द्र शाह (बालेन) प्रधानमंत्री बने लेकिन एक के बाद एक उनकी तरफ से दिए जा रहे बयानों पर विवाद खड़े हो रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार भारत-नेपाल सीमा विवाद पर एक हैरान कर देने वाला बयान दिया है। जिस पर काफी विवाद पैदा हो गया है। बालेन शाह ने कहा है कि सीमा पर अतिक्रमण केवल एक तरफ से नहीं बल्कि दोनों तरफ से हुआ है। भारत ने नेपाल की जमीन पर कब्जा किया है तो नेपाल ने भी भारतीय जमीन पर कब्जा किया है। हालांकि बालेन शाह ने उन जगहों के स्टीक नाम या विवरण नहीं दिया लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन मुद्दों को उलझाने की बजाय भारत-नेपाल मेज पर बैठकर वार्ता करेंगे और इसे सुलझा लेंगे। दूसरी ओर, प्रधानमंत्री के इस अप्रत्याशित बयान के बाद नेपाल की संसद में भारी हंगामा शुरू हो गया है। मुख्य विपक्षी दल 'नेपाली कांग्रेस' ने पीएम बालेन शाह के इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है, नेपाली कांग्रेस के मुख्य सचेतक ने इस बयान को बेहद संवेदनशील और आपत्तिजनक बताते हुए प्रधानमंत्री से तुरंत सबूत और स्पष्टीकरण की मांग की है। विपक्ष का कहना है कि देश के प्रधानमंत्रियों को ऐसे नाजुक और कूटनीतिक मामलों पर बिना पुख्ता सबूतों के हल्के में बयान नहीं देना चाहिए। विपक्ष ने मांग की है कि यदि सरकार इसके सबूत पेश नहीं कर पाती तो इस बयान को संसद के रिकॉर्ड से तुरंत हटाया जाए। विवाद के बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट भी दी कि सीमापार कब्जे से मतलब नो मैन्स लैंड के उन इलाकों से है जहां दोनों देशों के लोग रहकर खेती करते हैं। नेपाल और भारत के बीच कुछ समय से लिपुलेख और दूसरे इलाकों को लेकर तनाव देखा गया है। नेपाल के भारतीय इलाकों पर हक जताने के चलते दोनों देशों के बीच यह तनाव आया है। लिपुलेख पर नेपाल ने दावा ठोक कर भारत को नाराज किया है क्योंकि यह दशकों से भारतीय इलाका है। बॉर्डर के अलावा व्यापार के मुद्दे के भी दोनों पड़ोसी देशों में तनातनी की स्थिति देखी गई है। बालेन शाह ने आम चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने के बाद इस साल 27 मार्च को नेपाल के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। पीएम बनने के बाद से वह न तो किसी विदेश यात्रा पर गए है और ना ही यादा विदेशी मेहमानों से मिले हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री ने हास्यास्पद बात यह कही कि लिपुलेख, लिम्पिया धुरा और कालापानी मुद्दे पर भारत और चीन से ही नहीं बल्कि ब्रिटेन सरकार से भी बात की है। ब्रिटेन को भी इसमें मध्यस्थता करनी चाहिए क्योंकि यह विवाद उस समय से जुड़ा है जब अंग्रेज इस इलाके को छोड़कर गए थे। भारत का विदेश मंत्रालय पहले ही कह चुका है कि नेपाल का दावा ऐतिहासिक तथ्यों और सबूतों पर आधारित नहीं है और यह स्वीकार्य नहीं है। बालेन शाह के प्रधानमंत्री बनने के बाद से भारत और नेपाल के बीच पारंपरिक, कूटनीतिक और रणनीतिक संबंधों में काफी असहजता देखी जा रही है। बालेन शाह ने भारतीय विदेश सचिव को समय देने से इंकार किया। जिसके चलते भारत को यह दौरा टालना पड़ा। नेपाल में यह परम्परा रही है कि पद संभालने के बाद वहां के प्रधानमंत्री भारत का दौरा करते हैं लेकिन बालेन शाह ने यह घोषणा कर रखी है कि वह अपने कार्यकाल के पहले वर्ष में किसी भी देश का दौरा नहीं करेंगे। बालेन शाह को सत्ता संभाले कुछ महीने ही हुए हैं कि शपथ लेने के दो महीने के भीतर उनके दो मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। इन दोनों मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। बालेन शाह ने 100 सूत्री सुधार एजेंडा लॉन्च किया था लेकिन इसमें से 88 वादे अधूरे पड़े हैं। उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जो जेन जी युवाओं को रास नहीं आ रहे और युवा सवाल उठा रहे हैं कि अगर यही सब होना है तो नई राजनीति में क्या फर्क है। उनकी अपनी ही पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेताओं ने भी खुलेआम सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। बालेन शाह अध्यादेशों के जरिये ही सरकार चला रहे हैं क्योंकि ऊपरी सदन में उनका एक भी सदस्य नहीं है। भारत ने हमेशा संकटकाल में नेपाल की मदद की है। भूकंप की त्रासदी हो या कोरोना महामारी, भारत ने बढ़-चढ़कर बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए नेपाल की हर संभव मदद की है। अच्छा होता बालेन शाह राजनीतिक परिपक्वता का परिचय देते और भारत से संबंधों को सुधारने और मजबूत बनाने की राह पर आगे बढ़ते लेकिन उन्होंने भी अति राष्ट्रवादी नीति अपनाकर संबंधों में जहर घोल दिया है।

सम्पादकीय...

वन्यजीव सुरक्षा की दिशा में

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण, वन संवर्धन एवं जैव विविधता के संरक्षण हेतु निरंतर व्यापक एवं अभिनव प्रयास किये जा रहे हैं। वृक्षारोपण अभियान, आर्द्र भूमि संरक्षण, वन्यजीव सुरक्षा तथा नवीन तकनीकों के उपयोग से वृक्षावरण/वनावरण बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश में इस वर्ष 35 करोड़ पौधरोपण अभियान की तैयारियाँ भी तेज कर दी गई है। विभागीय पौधशालाओं में 52.46 करोड़ पौधों की उपलब्धता है। वृक्षारोपण अभियान को सफल बनाने में कृषकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। कृषकों को वृक्षारोपण से होने वाले आर्थिक एवं पर्यावरणीय लाभों की जानकारी दी जा रही है। कार्बन फाइनेंसिंग के माध्यम से उनकी आय में वृद्धि के प्रति जागरूक किया जाता है। कृषि भूमि पर स्थानीय जलवायु एवं मृदा के अनुरूप जामुन, महुआ, आंवला, चिरौंजी, आम आदि उपयोगी एवं आर्थिक दृष्टि से लाभकारी प्रजातियों के पौधे रोपित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। साथ ही तालाबों एवं जलस्रोतों के किनारे छायादार तथा फलदार पौधों का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण एवं जल संरक्षण को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में विगत नौ वर्षों में प्रदेशवासियों के सहयोग तथा विभिन्न विभागों के समन्वित प्रयासों से प्रदेश में 243 करोड़ से अधिक पौधों का रोपण किया गया है। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में जनसहभागिता सुनिश्चित करने हेतु प्रदेश की 27,000 ग्राम पंचायतों में ग्रीन चौपाल का आयोजन किया गया, इससे ग्रामीण स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ी है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में पहली बार वन क्षेत्र के बाहर हरीतिमा बढ़ाने एवं कृषकों की आय में वृद्धि कार्बन क्रेडिट की धनराशि वितरित किये जाने जैसे अभिनव प्रयास भी किये गये है। प्रदेश सरकार के इन सतत प्रयासों एवं बेस्ट प्रैक्टिसेस के सकारात्मक परिणाम स्वरूप भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून द्वारा प्रकाशित 'स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट-2023' के अनुसार वर्ष 2015 से 2023 के मध्य उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षावरण में लगभग 3.38 लाख एकड़ क्षेत्र की वृद्धि दर्ज की गयी है। यह उपलब्धि प्रदेश सरकार की पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता एवं जनसहभागिता आधारित कार्यप्रणाली का प्रत्यक्ष प्रमाण है। आर्द्र भूमि संरक्षण के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश निरंतर उल्लेखनीय उपलब्धियाँ प्राप्त कर रहा है। प्रदेश में अब तक 12 रामसर साइट घोषित हो चुकी है, जिसके साथ उत्तर प्रदेश देश में दूसरा स्थान प्राप्त कर चुका है। प्रदेश की अन्य अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैण्ड्स की पहचान कर उन्हें रामसर साइट घोषित करवाने हेतु प्रस्ताव भी बनाये जा रहे है। प्रदेश के आर्द्र भूमि, जैव विविधता संरक्षण, जल संरक्षण तथा पर्यावरण संतुलन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। वन विभाग द्वारा इनके संरक्षण हेतु विशेष प्रयास किये जा रहे है। नवीन योजनाओं के अंतर्गत वन एवं वन्यजीव सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर भी विशेष बल दिया गया है। प्रदेश में वन बल आधुनिकीकरण हेतु एक नई योजना स्वीकृत की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत आधुनिक तकनीक, निगरानी प्रणाली एवं संसाधनों के माध्यम से वन एवं वन्यजीव संरक्षण को और अधिक प्रभावी बनाया जायेगा। मानव-वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए वन विभाग द्वारा विभिन्न जनपदों में वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर स्थापित किये जा रहे है। मेरठ, महाराजगंज, चित्रकूट एवं पीलीभीत में चार वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर निर्माणाधीन है।

विमर्श-हमारे लिए आज बांगडुंग स्पिरिट की आवश्यकता है

ऐप्सो के राष्ट्र महासचिव अनीश अंकुर ने अपने संबोधन में कहा कि 1955 में 29 नवस्वाधीन देशों ने इंडोनेशिया के बांगडुंग में इकट्ठा होकर ऐतिहासिक मोड़ लाने वाला काम किया। पहली बार नए स्वतंत्र हुए देशों ने सामूहिक रूप से साम्राज्यवादी देशों को चुनौती देते हुए कहा कि अपने देश के भाग्य का निर्धारण हम करेंगे कोई दूसरा नहीं। हमारे संसाधनों का शोषण, उत्पीड़न अब बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। इस सम्मेलन को बनाने में भारत के जवाहर लाल नेहरू, इंडोनेशिया के सुकर्णो, मिश्र के अब्दुल गमाल नासिर और युगोस्लाविया के मार्शल टीटो का योगदान प्रमुख था। बांगडुंग ने भारत चीन के पंचशील सिद्धांतों की तर्ज पर दसशील सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। बांगडुंग की भावना आगे चलकर 1961 बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष आंदोलन, 1966 में ट्राई कॉन्टिनेंटल कॉन्फ्रेंस के रूप में आगे बढ़ी। लेकिन सी.आई.ए. और अन्य देशों के इंटेलीजेंस एजेंसियों ने 1960 में कांगो के राष्ट्रपति पैट्रिस लुमुंबा के हत्या कराई और जिस सुकर्णो ने बांगडुंग सम्मेलन कराया उनका तख्तापलट कराकर दस लाख कम्युनिस्टों की हत्या की गई। बांगडुंग सम्मेलन कराने की यह सजा दी गई थी। बांगडुंग सम्मेलन के बहुत सफल न होने का कारण यह था कि बांगडुंग के नेतागण साम्राज्यवाद से तो लड़ना चाहते थे पर उसके सामाजिक आर्थिक ढांचे से पार नहीं पाने का उनके पास कार्यक्रम न था। नवउपनिवेश देशों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर न था। पर आज लगता है भौतिक परिस्थितियां तैयार हो रही है। इसका इस्तेमाल करने की जरूरत है। साथ ही तीसरी दुनिया में थोपे गए ऋण संकट ने भी बांगडुंग के सफल होने में बाधा पहुंचाई। शिक्षाविद् कुमार सर्वेश ने अपने संबोधन में कहा आज का अंतर्राष्ट्रीय समय पहले की तुलना में ज्यादा कठिन व जटिल है। हमारे लिए आज बांगडुंग स्पिरिट की आवश्यकता है। बांगडुंग के मंच ने चीन को रिस्पेक्टिबिलिटी दिलाई। 2014 तक भारत की विदेश नीति में अमेरिका की ओर झुकने के बावजूद एक संतुलन कायम करने की कोशिश की थी लेकिन पिछले दस ग्यारह साल से अमेरिका की ओर झुकाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी अफगानिस्तान, बांग्लादेश आदि में हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ी है। यूक्रेन में हमने थोड़ा संतुलन स्थापित करने की कोशिश की है। आज के जो अमेरिकी राष्ट्रपति है ऐसा अनप्रीडिक्टेबल है जो सुबह कुछ बोलते है शाम में कुछ। तीसरी दुनिया के देश संयुक्त राष्ट्र में जिस लोकतांत्रिकरण की बात कर रहे है वह साउथ-साउथ सहयोग के बगैर नहीं संभव है। तीसरी दुनिया के देशों को उनके साम्राज्यवाद से खतरा है। चीन का ट्रेड सरप्लस उसके रणनीतिक स्पेस को बढ़ाते हुए उसके प्रभाव को बढ़ाने की ओर ले जा रहा है। पटना विश्वविद्यालय में लोक प्रशासन के असिस्टेंट प्रोफेसर सुधीर कुमार ने कहा पंचशील समझौतों के आधार पर बांगडुंग ने अपना कार्यक्रम तय किया था। आज फिर से तीसरी दुनिया के देशों के सामने अपने संसाधनों के नियंत्रण के लिए साम्राज्यवादी देशों के खिलाफ मुकाबला किया जा सके। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता रामलाला सिंह ने अपने संबोधन में कहा नेहरू जी ने भारत को पैरों पर खड़ा करने के लिए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण के उसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बदला। बोकारो, भेल जैसे उद्योगों का सार्वजनिक क्षेत्र में लाकर पब्लिक सेक्टर को मजबूत बनाया। नेहरू जी के योगदान को हमें समझने के जरूरत है। यदि वे होते तो देश की दुर्दशा नहीं होती। गुटनिरपेक्ष देशों का आंदोलन इतना कमजोर नहीं होता। अमेरिका नहीं चाहता कि कोई उसकी इच्छा के बगैर दूसरा देश किसी से व्यापार करे। वह उसपर प्रतिबंध लगा देता है। सभा को पटना जिला किसान सभा के गोपाल शर्मा ने बताया बांगडुंग का पहला सिद्धांत यह था कि यू एन चार्टर का सम्मान, क्षेत्रीय अखंडता को अक्षुण्ण रखना, एक दूसरे पर हमला नहीं करना। बांगडुंग का परिणाम था उपनिवेशवाद पर करारा प्रहार। स्वतंत्र देशों की अपनी स्वाधीन विदेश नीति होगी। नेहरू बहुत बड़े नेता थे। सामाजिक कार्यकर्ता प्रीति सिंह ने बताया नेहरू जी ने भारत की बहुत मजबूत नींव रखी थी लेकिन आज उसे धराशाई किया जा रहा है। बांगडुंग सम्मेलन में नेहरू जी के नेतृत्व में यह समझ बनी के गुलामी से मुक्ति पाए देशों को एक दूसरे की संप्रभुता की रक्षा करनी होगी। आज हमारा देश इजरायल जैसे गलत देश का साथ दे रहा है। भारत में आंतरिक स्वतंत्रता को समाप्त किया जा रहा है। कथाकार चितरंजन भारती ने अपने संबोधन में कहा इस बहाने हम इतिहास को खंगालने का काम किया है। आज सारे के सारे सार्वजनिक उपक्रम किसी निजी कंपनी को देने के लिए बंद किया जा रहा है। सरकारी संपत्ति को सुनियोजित ढंग से प्राइवेट कंपनी को दिया जा रहा है। सार्वजनिक उद्यम में प्रशासनिक कमियां थी उन कमियों को बढ़ाचढ़ाकर दिखाया गया ताकि निजी क्षेत्र के लिए जगह बनाया गया। आजकल 12 घंटे तक नौकरी करना पड़ता है कैसे फिर किताब पढ़ेंगे, पत्र-पत्रिका देखेंगे या कोई और काम करेंगे। इतना खटने पर भी कितना कम पैसा मिलता है। उनकी माली हालत बेहद खराब है। अध्यक्षीय वक्तव्य देते हुए ऐप्सो के राष्ट्र महासचिव रामबाबू कुमार ने कहा हमलोग नेहरू जवाहर लाल नेहरू वामपंथी रुझान के लिबरल डेमोक्रेट हैं। कांग्रेस के अंदर वामपंथी धारा को मजबूत बनाने में नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का प्रमुख योगदान था। फैजाबाद में कांग्रेस को सोशलिस्ट मोड़ देने की कोशिश की थी। समाजवादी दिशा में देश को ले जाना हमारे संविधान की आत्मा है। 1949 में काउंसिल फॉर म्युचुअल असिस्टेंस बना था। 1955 में वारसॉ पैक्ट बना। 1956 आते आते जिस गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो बुनियाद रखा उसने शीत युद्ध के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नव आजाद देशों के प्रगतिशील राष्ट्रवाद का मंच यह बना था। 1977 के बाद मोरारजी देसाई ने फिलीस्तीन को छोड़ इजरायल के साथ संबंध बढ़ाया। 1983 में गुट निरपेक्ष देशों का सम्मेलन होता है जिसमें इंदिरा गांधी और यासिर अराफात साथ साथ आते हैं। कार्यक्रम का संचालन रौशन प्रकाश ने किया। धन्यवाद ज्ञापन आनंद शर्मा ने किया। कार्यक्रम में शामिल प्रमुख लोगों में रमेश सिंह, आनंद शर्मा, संदीप, विकास, विनय लाल, प्रमोद नंदन, रामजी यादव, छात्र नेता सुधीर, रोहित शर्मा, प्रिंस राज, भोला पासवान, प्रमोद नंदन, गौरव, विपिन आदि शामिल थे।

> फैजाबाद में कांग्रेस को सोशलिस्ट मोड़ देने की कोशिश की थी। समाजवादी दिशा में देश को ले जाना हमारे संविधान की आत्मा है। 1949 में काउंसिल फॉर म्युचुअल असिस्टेंस बना था। 1955 में वारसॉ पैक्ट बना। 1956 आते आते जिस गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो बुनियाद रखा उसने शीत युद्ध के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । नव आजाद देशों के प्रगतिशील राष्ट्रवाद का मंच यह बना था। 1977 के बाद मोरारजी देसाई ने फिलीस्तीन को छोड़ इजरायल के साथ संबंध बढ़ाया। 1983 में गुट निरपेक्ष देशों का सम्मेलन होता है जिसमें इंदिरा गांधी और यासिर अराफात साथ साथ आते हैं। कार्यक्रम का संचालन रौशन प्रकाश ने किया।

महिला सशक्तिकरण से सामाजिक विकास को सशक्त कर रहा कानपुर देहात

महिला सशक्तिकरण किसी भी प्रगतिशील समाज का मूल आधार होता है और जब महिलाएं आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से सुदृढ़ होती हैं, तभी एक समृद्ध एवं संतुलित समाज का निर्माण संभव हो पाता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रदेश सरकार के कुशल नेतृत्व व मार्गदर्शन में जनपद कानपुर देहात में महिला कल्याण विभाग द्वारा सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी संचालन किया जा रहा है। इन योजनाओं का मुख्य लक्ष्य महिलाओं एवं बालिकाओं के जीवन स्तर में सुधार लाना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना तथा एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करना है। वित्तीय वर्ष 2025-26 तक जनपद में इन योजनाओं के अंतर्गत बड़ी संख्या में लाभार्थियों को सीधे लाभान्वित किया गया है, जो प्रशासनिक कार्यकुशलता, पारदर्शिता और संवेदनशीलता को रेखांकित करता है। इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में जिला प्रशासन ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसके परिणामस्वरूप धरातल पर व्यापक और सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। जनपद कानपुर देहात में संचालित योजनाओं में सबसे प्रमुख निराश्रित महिला पेंशन योजना की बात करें तो यह योजना उन महिलाओं के लिए एक जीवनरेखा के समान सिद्ध हो रही है, जो आर्थिक रूप से अत्यंत कमजोर है और जिनके पास जीविकोपार्जन का कोई स्थायी साधन नहीं है। वित्तीय वर्ष 2025-26 तक जनपद कानपुर देहात में इस योजना के अंतर्गत कुल 35,945 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। लाभार्थी महिलाओं की यह संख्या दर्शाती है कि बड़ी संख्या में महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने जीवन को आर्थिक रूप से सुरक्षित बना रही हैं। इस योजना के माध्यम से प्रदेश सरकार न केवल नियमित आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि समाज की वृद्ध, विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का एक वास्तविक अवसर भी दे रही है। इस आर्थिक संबल से महिलाओं की दूसरों पर निर्भरता कम हुई है और वे स्वावलंबन की ओर अग्रसर हुई हैं। इसी कड़ी में दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है, जिसका मूल उद्देश्य बालिकाओं के जन्म से लेकर उनकी उच्च शिक्षा हेतु उनके स्नातक होने तक आर्थिक सहायता प्रदान करना है। जनपद कानपुर देहात में इस योजना के अंतर्गत अब तक 3,342 बालिकाओं को सीधे लाभान्वित किया जा चुका है। यह योजना बालिका भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने तथा बालिकाओं के प्रति समाज की रूढ़िवादी सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक सिद्ध हुई है। इस योजना के तहत विभिन्न चरणों में बालिकाओं को कुल 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जो उनके पोषण, शिक्षा एवं बेहतर स्वास्थ्य पर सीधा सकारात्मक प्रभाव डाल रही है। इसके परिणामस्वरूप जनपद में बालिकाओं की शिक्षा दर में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की जा रही है और वे भविष्य में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं। जनपद में कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे और किसी कारणवश अपने अभिभावकों से वंचित हुए बच्चों की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है। कानपुर देहात में इस योजना के अंतर्गत अब तक 1,370 लाभार्थियों को सहायता प्रदान की गई है। यह योजना समाज के सबसे कमजोर और संवेदनशील वर्ग के बच्चों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच के रूप में कार्य कर रही है। इसके माध्यम से ऐसे बच्चों को शिक्षा, पोषण एवं समुचित देखभाल की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे उनका भविष्य पूरी तरह सुरक्षित हो सके। इन तीनों प्रमुख योजनाओं के आंकड़े यह प्रमाणित करते हैं कि जनपद में महिला कल्याण विभाग की सक्रियता से और प्रशासन की तत्परता से अंतिम पायदान पर खड़े लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर समीक्षा बैठकों का आयोजन कर योजनाओं की प्रगति की निरंतर निगरानी की जाती है तथा लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाता है, जिससे कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित न रहे। प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के सर्वांगीण विकास, सुरक्षा, शिक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार किया गया है, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर स्वरोजगार तक के लिए विशेष पहल शामिल हैं। इसी उद्देश्य से 'मिशन शक्ति' जैसा एक व्यापक अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन सुनिश्चित करना है। इसके तहत थानों में महिला हेल्प डेस्क, वन स्टॉप सेंटर और महिला बीट पुलिस अधिकारी जैसी उत्कृष्ट व्यवस्थाएं की गई हैं। संकट में फंसी, प्रताड़ित या किसी भी प्रकार की आपातकालीन सहायता की आवश्यकता वाली महिलाओं और बालिकाओं के लिए 24 घंटे संचालित रहने वाली 181 महिला हेल्पलाइन टोल-फ्री नंबर की सुविधा दी गई है, जिसे अब उत्तर प्रदेश पुलिस की आपातकालीन सेवा 112 के साथ पूरी तरह एकीकृत कर दिया गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला सामर्थ्य योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत महिलाओं को कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प और छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए निरंतर प्रोत्साहित किया जाता है। इसी प्रकार, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की आय को बढ़ाकर प्रति वर्ष एक लाख रुपये से अधिक करने के उद्देश्य से 'लखपति दीदी योजना' प्रभावी रूप से काम कर रही है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत कर रही है। गंभीर अपराधों की शिकार महिलाओं और बालिकाओं को चिकित्सा उपचार, पुनर्वास और आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष का गठन किया गया है। गरीब परिवारों की बेटियों, विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं के विवाह की आर्थिक समस्या को दूर करने के लिए सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से सरकार द्वारा बड़ा अनुदान और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जिला स्तर पर इन कार्यक्रमों को गति देने के साथ-साथ 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' अभियान, 'हब फॉर इम्पावरमेंट ऑफ वूमेन' जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं, जो महिलाओं के सशक्तिकरण को धरातल पर उतार रही है। इसके साथ ही वृद्ध महिलाओं के लिए वृद्ध महिला आश्रम, राजकीय महिला शरणालय व संरक्षण गृह तथा शक्ति सदन जैसी संस्थाएं निराश्रित महिलाओं को सुरक्षित आश्रय प्रदान कर रही हैं। सामाजिक सुधार की दिशा में एक अनोखा प्रयास करते हुए, 35 वर्ष से कम आयु की पति की मृत्युपरांत निराश्रित महिला से विवाह करने पर दम्पत्ति को पुरस्कार देने की योजना तथा पति की मृत्युपरांत निराश्रित महिला की पुत्री से विवाह हेतु विशेष अनुदान योजना भी संचालित है। दहेज से पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय और सहायता देने के लिए आर्थिक एवं कानूनी सहायता योजना चलाई जा रही है। कामकाजी महिलाओं के लिए सखी निवास हॉस्टल और निराश्रित महिलाओं के लिए 1000 बेड की क्षमता वाले कृष्णा कुटीर आश्रय सदन जैसी भव्य बुनियादी ढांचागत व्यवस्थाएं प्रदेश स्तर पर की गई हैं। इन सभी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ग्रामीण और शहरी स्तर पर जागरूकता का व्यापक प्रसार किया जा रहा है ताकि जानकारी के अभाव में कोई भी पात्र लाभार्थी योजना का लाभ उठाने से न छूटे। इसके लिए प्रचार-प्रसार के विभिन्न माध्यमों का उपयोग जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, योजनाओं के क्रियान्वयन में आधुनिक तकनीकी साधनों का उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने कदम ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, साउथ पैंचशील एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/[illegible])

हरियाणा के रायपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने तेलंगाना स्थापना दिवस पर दी शुभकामनाएं

चंडीगढ़ ।(संवाददाता) हरियाणा के रायपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने तेलंगाना राय के स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देते हुए कहा कि 'विकसित भारत 2047' के संकल्प को साकार करने की दिशा में तेलंगाना और हरियाणा दोनों राय महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। रायपाल आज यहां हरियाणा लोक भवन में तेलंगाना स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में अधिकारियों एवं तेलंगाना समुदाय के सदस्यों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिकारियों सहित हरियाणा में निवास कर रहे तेलंगाना समुदाय के सदस्य उपस्थित रहे। प्रो. असीम कुमार घोष ने कहा कि 2 जून, 2014 को तेलंगाना राय का गठन लाखों लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं की पूर्ति का ऐतिहासिक क्षण था। स्थापना के बाद से तेलंगाना देश के सबसे गतिशील और प्रगतिशील रायों में से एक के रूप में उभरा है तथा कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी, आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और औद्योगिक विकास के क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के लोगों की मेहनत, नवाचार और दृढ़ संकल्प ने राय को देश की आर्थिक प्रगति और तकनीकी विकास में अग्रणी योगदानकर्ताओं में शामिल कर दिया है। तेलंगाना की विकास यात्रा न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि यह भारत की लोकतांत्रिक एवं संघीय व्यवस्था की मजबूती को भी दर्शाती है। हरियाणा और तेलंगाना के बीच मजबूत संबंधों का उल्लेख करते हुए रायपाल ने कहा कि भौगोलिक दूरी के बावजूद दोनों राय समावेशी विकास, किसानों और युवाओं के कल्याण तथा प्रत्येक नागरिक की उन्नति एवं प्रगति के साझा उद्देश्य से जुड़े हैं।

प्रो. असीम कुमार घोष ने विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना के लोग भविष्य में भी नई उपलब्धियां हासिल करते रहेंगे और राष्ट्र की प्रगति, समृद्धि तथा गौरव में अपना अमूल्य योगदान देते रहेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्य सूचना आयुक्त श्री टी.वी.एस.एन. प्रसाद, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजा शेखर वुंदरु, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (मानवाधिकार एवं वाद-विवाद) डॉ. सी.एस. राव, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राय सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डॉ. एम. रवि किरण, रायपाल के सचिव श्री विजयकुमार भाविकट्टी, रायपाल के एडीसी श्री धीरज सेतिया व श्री पी. भरत, अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा हरियाणा में निवास कर रहे तेलंगाना समुदाय के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

सरकारी अस्पतालों में साफ-सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को पीपीपी मोड पर करवाया जाएगा : आरती सिंह राव

(संवाददाता)

चरखी दादरी जिले में निर्माणाधीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का नाम स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम के नाम पर होगा कहा ,महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा

चंडीगढ़ । हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि प्रदेश सरकार का मुख्य फोकस राय की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़, सुरक्षित और आधुनिक बनाने पर है। आज चंडीगढ़ में अपने सरकारी आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि राय के सरकारी अस्पतालों में प्रबंधन को बेहतर करने के लिए साफ-सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड पर सौंपा जाएगा। इस कदम का मुख्य उद्देश्य अस्पतालों में महिला मरीजों, नर्सों, डॉक्टरों और अन्य स्टाफ की सुरक्षा को बेहद मजबूत करना है। स्वास्थ्य मंत्री ने महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसी कड़ी में उन्होंने कुरुक्षेत्र के लोक नायक जयप्रकाश नागरिक अस्पताल में एक नाबालिग लड़की के साथ हुए यौन उत्पीड़न के मामले का जिक्र करते हुए बताया कि आरोपी कंसल्टेंट के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसकी सेवाएं समाप्त कर दी हैं। आरती सिंह राव ने जानकारी दी कि चरखी दादरी जिले में निर्माणाधीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का नाम देश के महान स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम के नाम पर रखा जाएगा। इस नामकरण के लिए उन्होंने केंद्र सरकार और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह इस नामकरण के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे।

स्वास्थ्य मंत्री ने जोर देकर कहा कि ऐसे प्रयासों से हमारी युवा पीढ़ी को देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों के सर्वोच्च बलिदान और संघर्षों को करीब से जानने का अवसर मिलेगा। यह मेडिकल कॉलेज न केवल चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेगा, बल्कि युवाओं के लिए एक बड़ा प्रेरणा स्रोत भी बनेगा, जिससे वे देश सेवा के प्रति प्रेरित होंगे। राय के नागरिकों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए आरती सिंह राव ने कहा कि सरकार की शीर्ष प्राथमिकता सभी जिलों में गायनेकोलॉजिस्ट, एनेस्थीसिया और पीडियाट्रिशन (बाल रोग विशेषज्ञ) की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। उनका मुख्य फोकस सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में महिलाओं और बच्चों को उनके घर के नजदीक ही इलाज की सुविधाएं प्रदान करना है। उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में चिकित्सा ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार ने करीब 104.16 करोड़ रुपये के विकास कार्य शुरू किए हैं। इसके साथ ही 15वें वित्त आयोग के तहत राय में 766 नए स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण को मंजूरी दी गई है, जिसमें ग्रामीण और कस्बा स्तर पर स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत करने के लिए 597 उप-स्वास्थ्य केंद्र, 51 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी), 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और 111 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ सेंटर शामिल हैं। मरीजों को आधुनिक सुविधाएं और सस्ती दवाएं देने के प्रयासों को रेखांकित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि हृदय रोगियों की सहूलियत के लिए राय के 600 स्वास्थ्य संस्थानों में टेली-ईसीजी सेवाएं शुरू की जा रही हैं। इसके अलावा आम जनता को सस्ती एवं उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं उपलब्ध कराने के लिए 23 जिला अस्पतालों में अमृत फार्मेसी स्थापित की गई हैं।

इन फार्मेसियों में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वे स्वयं भी समय-समय पर औचक निरीक्षण कर स्थिति का जायजा ले रही हैं। पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक तकनीक को स्वास्थ्य क्षेत्र से जोड़ते हुए आरती सिंह राव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में ग्रीन एनर्जी को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी दिशा में अब सरकारी अस्पतालों में सोलर प्लांट लगाने की तैयारी की जा रही है, और हरियाणा सरकार भी इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए तेजी से कदम आगे बढ़ा रही है।

इस वर्ष हरियाणा में अनाज भंडारण के लिए 20 लाख मीट्रिक टन क्षमता के नए गोदाम बनाए जाएंगे - मुख्यमंत्री

(संवाददाता)

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विजन-2047 के तहत खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अगले 5 साल के रोडमैप व कार्ययोजना की समीक्षा बैठक में दिए विस्तृत दिशा-निर्देश

चंडीगढ़ । हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसान द्वारा मेहनत से उगाए गए अनाज को खराब होने से बचाने के लिए हरियाणा में अनाज भंडारण की समुचित व्यवस्था की जाएगी। इसके अंतर्गत इस साल हरियाणा में 20 लाख मीट्रिक टन क्षमता के नए गोदाम बनाए जाएंगे जिसके लिए अधिकारी पूरी तैयारी करके लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में जुट जाएं। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश मंगलवार को हरियाणा सिविल सचिवालय में हरियाणा विजन-2047 के तहत खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अगले 5 साल के रोडमैप व कार्ययोजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री जे गणेशन ने बताया कि अनाज का खुले में भंडारण अथवा उचित भंडारण के अभाव के कारण प्रदेश में अनाज का 4 से 5 प्रतिशत तक नुकसान हो जाता है। इस नुकसान से बचने के लिए कवर्ड स्टोरेज की व्यवस्था करनी आवश्यक है। उन्होंने बताया कि इस समय प्रदेश में गेहूं का 115 लाख मीट्रिक टन, चावल का 71 लाख एमटी, फल व सब्जियों का 110 लाख एमटी तथा दूध व अन्य डेयरी उत्पादों का 115 लाख एमटी उत्पादन होता है। राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा में हरियाणा का योगदान लगभग 25 प्रतिशत है। इस समय हरियाणा में 66 लाख मीट्रिक टन अनाज भंडारण की क्षमता है जिसे 130 लाख एमटी तक बढ़ाने की आवश्यकता है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद्यान्न के नुकसान पर रोक लगाने के लिए कवर्ड स्टोरेज के निर्माण, कोल्ड स्टोरेज की क्षमता बढ़ाने और उपलब्ध संसाधनों का उचित इस्तेमाल करने की कार्ययोजना बनाई जाए। सभी संबंधित विभागों के आपसी समन्वय के साथ इस वर्ष पीपीपी मोड में 20 लाख मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम बनाने का लक्ष्य पूरा किया जाए ताकि अनाज को खराब होने से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अनाज, बागवानी फसलों, सब्जियों तथा फलों के उचित भंडारण के लिए अगले 5 साल के भीतर एक ऐसी कार्ययोजना को मूर्त रूप दिया जाएगा जिससे उत्पादित खाद्यान्न का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बने गोदामों को ऊर्जा उत्पादन का भी माध्यम बनाया जाए। सभी गोदामों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर इन्हें ग्रिड से जोड़ा जाए ताकि बिजली का उत्पादन बढ़ाया जा सके। इसी प्रकार मंडियों व गोदामों में मजदूर की पीठ पर बोरी लादने की बजाय इस कार्य के लिए कन्वेयर बैल्ट अथवा अन्य तकनीकी व्यवस्था के लिए पायलेट प्रोजेक्ट शुरू किए जाएं। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री जे गणेशन ने फसल के नुकसान पर रोक लगाने तथा मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभाग द्वारा अगले 5 वर्षों के दौरान किए जाने वाले कार्यों का खाका प्रस्तुत करते हुए बताया कि इससे 3000 से 5000 करोड़ रुपये के नुकसान को रोका जा सकेगा। इस अवसर पर मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री जे गणेशन, डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की प्रधान सचिव श्रीमती अमनीत पी कुमार, मुख्यमंत्री के ओएसडी व स्वर्ण जयंती हरियाणा राजकोषीय प्रबंधन संस्थान के महानिदेशक डॉ. राज नेहरू तथा मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव श्री यशपाल यादव सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

हरियाणा ने एसजीएसटी) संग्रह की विकास दर के मामले में देश के सभी रायों में पहला स्थान हासिल किया

चंडीगढ़ ।(संवाददाता) हरियाणा ने मई 2026 के महीने में ÷राय माल और सेवा कर÷ (एसजीएसटी) संग्रह की विकास दर के मामले में देश के सभी रायों में पहला स्थान हासिल किया है। मई 2025 की तुलना में इस बार राय ने 22 प्रतिशत की शानदार विकास दर दर्ज की है, जबकि इस अवधि के दौरान एसजीएसटी संग्रह में राष्ट्रीय औसत विकास दर महज 6 प्रतिशत रही। इस सूची में हरियाणा के बाद मेघालय 19 प्रतिशत के साथ दूसरे, कर्नाटक 17 प्रतिशत के साथ तीसरे और गुजरात 16 प्रतिशत के साथ चौथे स्थान पर रहा। आबकारी एवं कराधान विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि मई के महीने में हरियाणा का शुद्ध राय जीएसटी (निपटान के बाद) संग्रह 4,456 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष के इसी महीने के संग्रह (3,649 करोड़ रुपये) से 807 करोड़ रुपये अधिक है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2026-27 के पहले दो महीनों में भी हरियाणा सभी रायों के बीच एसजीएसटी राजस्व की संचयी विकास दर (क्युमुलेटिव ग्रोथ रेट) में शीर्ष पर है। राय ने पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि की तुलना में 40 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्ज की है, जबकि चालू वित्तीय वर्ष के पहले दो महीनों के दौरान राय जीएसटी राजस्व की औसत राष्ट्रीय वृद्धि 23 प्रतिशत रही। यह पहली बार नहीं है जब राय ने ऐसा प्रदर्शन किया हो; हरियाणा लगातार एसजीएसटी राजस्व में उच्च विकास दर दर्ज कर रहा है। इससे पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 में भी हरियाणा ने राष्ट्रीय औसत 6 प्रतिशत के मुकाबले 22 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ देश में सबसे अधिक ग्रोथ रेट दर्ज की थी। राय के जीएसटी राजस्व में इस लगातार उच्च वृद्धि का श्रेय प्रदेश की बढ़ती अर्थव्यवस्था और कुशल कर-प्रशासन को दिया जा रहा है। विभाग द्वारा डेटा एनालिटिक्स पर आधारित प्रवर्तन (इन्फोर्समेंट), फर्जी करदाताओं के खिलाफ गहन अभियान, अनुपालन (कम्प्लायंस) में सुधार और राजस्व रिसाव को रोकने के लिए लगातार कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही, कर-प्रशासन को अधिक व्यापार-अनुकूल बनाने और करदाताओं की सुविधा के लिए भी विभाग प्रयासरत है। इसी कड़ी में, मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुपालन में, विभाग ने अब करदाताओं की सहूलियत के लिए पोर्टल पर उपलब्ध कराने के साथ-साथ कारण बताओ नोटिस (शो कॉज नोटिस) और सीमित आदेशों को पंजीकृत/स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी भेजना शुरू कर दिया है।

हरियाणा की चीनी मिलों को एक साल में घाटे से लाभ में लाना सुनिश्चित करें - मुख्यमंत्री

चंडीगढ़ । (संवाददाता) मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा की सभी सहकारी चीनी मिलों की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए इन्हें अगले एक साल में घाटे से निकालकर लाभ की स्थिति में लाना सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए उच्चाधिकारी एक-एक मिल की स्थिति की गहन समीक्षा करें और सभी कमियों को दूर करें। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने यह निर्देश मंगलवार को हरियाणा सिविल सचिवालय में हरियाणा विजन-2047 के तहत सहकारिता विभाग के अगले 5 साल के रोडमैप व कार्ययोजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। उन्होंने कहा कि वे तीन माह बाद विभाग की कार्य योजना की पुनः समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की सहकारी चीनी मिलों से किसानों के हित जुड़े हैं इसलिए इनका लाभकारी स्थिति में होना बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जब हरियाणा में निजी चीनी मिले लाभ की स्थिति में चल रही हैं तो फिर सहकारी चीनी मिलें घाटे में क्यों चल रही हैं। सरकार ने इस साल चीनी मिलों को 632 करोड़ रुपये की सहायता दी है। उन्होंने सहकारिता विभाग के प्रधान सचिव श्री पंकज यादव को सहकारिता विभाग की कार्यप्रणाली और मानव संसाधन का गहन विश्लेषण करते हुए विभाग का पूर्ण रूप से कायाकल्प करने को कहा। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि सहकारी चीनी मिलों में बैठे निठल्ले अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने समय-समय पर मिलों को अपडेट करने तथा एथनोल प्लांट्स लगाने के संबंध में भी व्यापक निर्देश दिए। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अगले वित्त वर्ष तक सभी सहकारी मिलों में कम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाने का उद्देश्य भी पूरा किया जाए।

अधिकारियों ने बताया कि सहकारी मिलों में कार्यकुशल कर्मचारियों की कमी है, क्योंकि कई कार्यों से संबंधित पढ़ाई केवल पुणे या कानपुर में होती है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि चीनी मिलों को कुशल युवा उपलब्ध करवाने के लिए आईटीआई में इससे संबंधित कोर्स शुरू करवाए जाएंगे। उन्होंने गन्ना बेचने आए किसानों का प्रतीक्षा समय कम होने पर संतुष्टि जाहिर की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य की जरूरतों के मद्देनजर प्रदेश में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए भी कार्ययोजना तैयार की जाए। इसके लिए उन्होंने नई डेयरी को-ओपरेटिव सोसायटी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को डेयरी शुरू करने व हरा चारा उगाने के लिए पंचायत की जमीन लीज पर दी जाए। इसके लिए उन्होंने पंचायत विभाग, पशुपालन विभाग तथा सहकारिता विभाग की संयुक्त कार्ययोजना तैयार करने को कहा। उन्होंने प्रदेश में पशुधन के लिए भविष्य में हरे व सूखे चारे की समुचित उपलब्धता के लिए भी व्यापक योजना बनाने के निर्देश दिए। श्री नायब सिंह सैनी ने हरको बैंक में 100 प्रतिशत पैक्स को कम्प्यूटरीकृत करने के निर्देश देते हुए सहकारी बैंकों में महिलाओं के खातों की जानकारी ली।

अधिकारियों ने बताया कि सहकारी बैंकों में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 15 हजार खाते हैं जिन्हें बढ़ाने के प्रतिवर्ष के लक्ष्य रखे गए हैं। स्वयं सहायता समूहों व वाइंट लायबिलिटी ग्रुप की महिलाओं को क्रेडिट सुविधा प्रदान की गई है और 145 करोड़ रुपये का ऋण देने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने लेबर एंड कंस्ट्रक्शन फेडरेशन के कार्यों की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि कुछ सोसायटीज को अधिक ऋण देने की बजाय अधिक सोसायटीज को ऋण उपलब्ध करवाया जाए ताकि अधिक लोगों को लाभ मिले। इसके लिए नियमों को लचीला बनाया जाए। अधिकारियों ने बताया कि अभी 3000 सोसायटीज के माध्यम से 2000 करोड़ रुपये के कार्य करवाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि अन्य संबंधित विभागों के समन्वय के साथ लक्ष्यों की प्राप्ति की योजना बनाई जाए। सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने ऋण वितरण का दायरा 130 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपये करने तथा कम से कम 100 पैक्स को इसी साल लाभ की स्थिति में लाने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि हरियाणा को-ओपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के परिवारों के लिए आवास बनाने हेतु प्रति परिवार 12.50 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। इस पर संबंधित परिवार को 7 प्रतिशत साधारण ब्याज अदा करना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कम आय वर्ग के ऐसे परिवारों को राहत देने के लिए ब्याज की दर को 7 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया जाए। इनके अलावा मुख्यमंत्री ने हरकोफैड, हैफेड व रजिस्ट्रार को-ऑपरेटिव सोसायटी सहित सहकारिता विभाग के अंतर्गत आने वाले अन्य उपक्रमों के कार्यों व भविष्य की योजनाओं की भी समीक्षा की तथा अगले 5 वर्षों में इनकी कायापलट के संबंध में अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश दिए।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला- मर्जी से वेश्यावृत्ति करना अब अपराध नहीं, पुलिस नहीं कर सकती परेशान

नई दिल्ली। भारतीय समाज में अमूमन जिस विषय पर खुलकर बात करने से कतराया जाता है उसी लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक युगांतरकारी और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत का यह आदेश सीधे तौर पर इंसानी गरिमा, व्यक्तिगत आजादी और मौलिक अधिकारों से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने करीब 70 साल पुराने इम्मोरल ट्रैफिक (प्रिवेंशन) एक्ट का बारीकी से अध्ययन करने के बाद साफ कर दिया है कि अगर कोई बालिग अपनी मर्जी से सेक्स वर्क यानी वेश्यावृत्ति का रास्ता चुनता है तो उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। जजों ने सख्त निर्देश दिए हैं कि ऐसे लोगों को सिर्फ उनके पेशे की वजह से न तो पुलिस परेशान करे और न ही उन पर कोई बेवजह कानूनी कार्रवाई की जाए। अदालत ने अपने फैसले में इस बात को पूरी तरह स्पष्ट किया है कि आईटीपीए कानून की मूल भावना क्या है शोषण के खिलाफ सुरक्षा- इस कानून का असली मकसद अपनी मर्जी से इस पेशे में शामिल वयस्कों को दंडित करना या प्रताड़ित करना नहीं है। मानव तस्करी पर वार- कानून का मुख्य उद्देश्य मानव तस्करी, जबरदस्ती, जालसाजी या किसी मजबूरी का फायदा उठाकर लोगों का किए जाने वाले व्यावसायिक शोषण को रोकना है। अगर किसी को धोखे से इस दलदल में धकेला जाता है तो वह कानूनन बेहद गंभीर अपराध बना रहेगा और दोषियों को सख्त सजा मिलेगी। अदालत ने आपसी सहमति से किए जाने वाले सेक्स वर्क और कानूनन प्रतिबंधित गतिविधियों के बीच का अंतर बिल्कुल साफ कर दिया है। बालिगों द्वारा आपसी रजामंदी से किया जाने वाला सेक्स वर्क अब कानूनी तौर पर अपराध के दायरे से बाहर है। वेश्यालय चलाना जुर्म - अपनी मर्जी से काम करने की छूट का मतलब यह कतई नहीं है कि कोठा या वेश्यालय चलाने की अनुमति मिल गई है। व्यावसायिक सेक्स एक्टिविटी के लिए अपनी संपत्ति या जगह का इस्तेमाल करने देना अभी भी एक दंडनीय अपराध है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि कानून की निम्नलिखित धाराओं के उल्लंघन पर पहले की तरह ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वेश्यालय चलाने या उसके लिए किराए पर जगह देने पर जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान है। किसी अन्य सेक्स वर्कर की कमाई के सहारे अपनी जिंदगी बसर करना या उसका फायदा उठाना अपराध है। किसी को इस धंधे में आने के लिए मजबूर करना, बहलाना-फुसलाना या उसकी तस्करी करना पूरी तरह प्रतिबंधित है। सार्वजनिक स्थानों, स्कूलों, अस्पतालों या धार्मिक स्थलों के आसपास इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देना पूरी तरह गैर-कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए कहा कि देश के हर नागरिक की तरह सेक्स वर्करों को भी समाज में सम्मान से जीने और पूर्ण कानूनी सुरक्षा पाने का पूरा अधिकार है। शीर्ष अदालत ने पुलिस और देश की सभी प्रशासनिक एजेंसियों को नसीहत दी है कि वे ऐसे मामलों में संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण अपनाएं तथा अपनी मर्जी से यह काम करने वाले वयस्कों के अधिकारों का हनन न करें।

4 जून को मॉनसून की दस्तक

केरल समेत कई राज्यों में भारी से बहुत भारी वर्षा

नई दिल्ली। मॉनसून की दस्तक का इंतजार अब खत्म होने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार, थोड़ी देरी के बाद मॉनसून 4 जून 2026 के आसपास केरल पहुंच सकता है। इसके साथ ही दक्षिण भारत के कई राज्यों में व्यापक बारिश की शुरुआत होने की संभावना है। मौसम एजेंसी ने अगले एक सप्ताह के दौरान केरल समेत दक्षिणी राज्यों में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान जताया है, जिससे गर्मी से राहत मिलने के साथ-साथ देश में बारिश के मौसम की आधिकारिक शुरुआत भी हो जाएगी। मौसम एजेंसी ने अगले एक हफ्ते में दक्षिणी राज्यों में बड़े पैमाने पर बारिश होने का अनुमान लगाया है, जिसमें केरल पर मॉनसून के आने का सबसे ज्यादा असर पड़ने की उम्मीद है। राज्य के कुछ अलग-अलग इलाकों में अगले छह से सात दिनों के दौरान 7cm से 20cm तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।

ट्रंप के दावों को नेतन्याहू ने दिखाया ठेंगा: इजराइल ने लेबनान पर बरसाए ड्रोन, 8 लोगों की मौत

दक्षिणी लेबनान में मंगलवार को इजराइल के ड्रोन हमलों में आठ लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति और उसका पुत्र व पुत्री शामिल हैं। ये हमले ऐसे समय में हुए हैं, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले कहा था कि इजराइल और हिजबुल्ला तनाव कम करने पर सहमत हो गए हैं। इजराइल ने सोमवार को बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमला करने की धमकी दी, जिससे लेबनान की राजधानी में दहशत फैल गई और हजारों लोग सुरक्षित क्षेत्रों की ओर जाने लगे। जवाब में हिजबुल्ला ने उत्तरी इजराइल पर कई रॉकेट दागे। इसके बाद ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की और मध्यस्थों के जरिये लेबनानी उग्रवादी समूह हिजबुल्ला के पदाधिकारियों से भी संपर्क साधा। उन्होंने घोषणा की कि «बेरूत में कोई सेना नहीं भेजी जाएगी। लेबनान की सरकारी नेशनल न्यूज एजेंसी ने मंगलवार को प्रसारित खबर में कहा कि इजराइली ड्रोन ने मरजायौन कस्बे को नबातीयेह शहर से

जोड़ने वाली सड़क पर खड़ी एक कार पर निशाना साधा, जिससे ईसाई बहुल शहर कलाया के रहने वाले एक डेंटिस्ट जेम्स कैरम और उनके पुत्र व पुत्री की मौत हो गई। लेबनानी सेना ने कहा कि नबातीयेह के बाहर हुए एक अन्य ड्रोन हमले में दो सैनिक मामूली रूप से घायल हो गए। नेशनल न्यूज एजेंसी की खबर के मुताबिक, जिब्शित गांव में हुए ड्रोन हमले में एक औषधशाला में काम करने वाले दो सीरियाई नागरिक मारे गए, जबकि पास के ही तोल गांव पर हुए एक अन्य हमले में दो लोगों की जान चली गई। तीसरा हमला हारूफ गांव के पास एक कार पर हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। खबर के अनुसार, सोमवार को इजराइल की ओर से माय्फादौन गांव में किए गए हवाई हमले में छह लोग मारे गए। हिजबुल्ला ने मंगलवार को कहा कि उसके लड़ाकों ने इजराइल सीमा से लगभग सात किलोमीटर दूर ह्दाथा गांव में घुसने की कोशिश कर रहे इजराइली सैनिकों पर टैंक-रोधी मिसाइल दागी। इजराइली सेना ने एक बयान में कहा कि उत्तरी इजराइल के कई इलाकों में हवाई हमलों के प्रति आगाह करने वाले सायरन बजे। बयान में कहा गया कि दक्षिणी लेबनान में जिस क्षेत्र में इजराइली सैनिक अभियान चला रहे हैं, वहां «एक ठिकाने पर हवाई हमले की खबर है», हालांकि उसमें किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। अमेरिका की मध्यस्थता में अप्रैल में संघर्ष-विराम समझौते पर सहमति बनने के बावजूद इजराइल और हिजबुल्ला लगातार एक-दूसरे पर हमले कर रहे हैं।

अखिलेश बोले- सत्ता से निराश लोग आत्मदाह को मजबूर

लखनऊ।(वेबवार्ता) सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि बिजली के बिल के नाम पर भाजपा 2027 के विधानसभा चुनाव के तिकड़मी खर्चों की व्यवस्था के लिए सरचार्ज (अधिभार) लगा रही है। भाजपा सरकार महंगाई बढ़ाकर जनता की जेब काट रही है। भाजपा की सरकार हर दिन महंगाई बढ़ा रही है। अखिलेश यादव ने जारी बयान में कहा कि भाजपा कभी डीजल, पेट्रोल, कभी बिजली और कभी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा रही है। भाजपा गरीब, किसान विरोधी है। 2027 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता भाजपा को हटाकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी, तभी महंगाई से निजात मिलेगी। वहीं, सपा अध्यक्ष ने एक्स के माध्यम से कहा कि भाजपा सरकार से निराशा इतनी बढ़ गई है कि नाउम्मीद होकर पीड़ित लोग आत्मदाह के लिए बाध्य हो रहे हैं।

आमने-सामने की टक्कर के बाद बस में लगी आग, 5 लोगों की मौत

सूरत। सूरत जिले के बारडोली के पास उवा गांव के पास आज एक बहुत ही दिल दहला देने वाला और भयानक हादसा हुआ। यह बड़ा हादसा तब हुआ जब महाराष्ट्र पासिंग की दो लग्जरी बसों की आमने-सामने टक्कर हो गई। शुरुआती खबरों के मुताबिक, इस भयानक हादसे में पांच यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोगों के गंभीर रूप से घायल होने का शक है। मिली जानकारी के मुताबिक, उवा गांव के पास से गुजर रही महाराष्ट्र पासिंग की दो बसों के बीच टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक बस सड़क पर पलट गई। हादसा होते ही पलटी हुई बस में अचानक भीषण आग लग गई। पूरी बस आग की लपटों में घिर गई, जिससे मौके पर भारी हंगामा और चीख-पुकार मच गई। बस में लगी आग की वजह से अंदर फंसे यात्रियों को निकालना मुश्किल हो गया। दूसरी बस का अगला हिस्सा भी इस भयानक टक्कर में तबाह हो गया। घटना की खबर मिलते ही बारडोली फायर डिपार्टमेंट की टीमें और लोकल पुलिस का काफिला मौके पर पहुंचा। फायरफाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया है और अंदर फंसे लोगों को निकालने के लिए युद्धस्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। घायलों को इलाज के लिए पास के हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है। अभी की गंभीर स्थिति को देखते हुए, डर है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है।

ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा हमला- लड़ूंगी या मर जाऊंगी, दिल्ली तक जाऊंगी; चुनाव में लगाया धांधली का बड़ा आरोप

कोलकाता। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने मंगलवार को मध्य कोलकाता में भाजपा की हालिया विधानसभा चुनावों में जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं पर कथित हमलों के विरोध में एक दिवसीय धरना शुरू किया। कोलकाता पुलिस द्वारा रानी रसमोनी रोड पर विरोध प्रदर्शन करने की टीएमसी की अपील को ठुकराए जाने के बाद वह एस्प्लेनेड के वाई-चैनल स्थित धरना स्थल पर पहुंचीं। बनर्जी ने मेगाफोन से भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि हमें मंच लगाने या माइक्रोफोन इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी गई। पूर्व मुख्यमंत्री के भाषण के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा नारे लगाने से विरोध प्रदर्शन में अफरा-तफरी मच गई। ममता ने कोलकाता में कहा कि

भाजपा ने बंगाल विधानसभा चुनाव जीतने के लिए 294 में से 177 सीटों पर मतगणना में धांधली की। उन्होंने दावा किया कि पुलिस टीएमसी कार्यकर्ताओं को प्रदर्शनों में भाग न लेने की धमकी दे रही है, मैं विरोध प्रदर्शन जारी रखूंगा। ममता ने कोलकाता में कहा कि पुनर्वास के बिना फेरीवालों को बेदखल करना टीएमसी सरकार की नीति नहीं थी, हमने मानवीय दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने कहा कि मैं इन कठिन समय में टीएमसी कार्यकर्ताओं का साथ नहीं छोड़ूंगी। ममता ने शुभेंदु अधिकारी की ओर इशारा करते हुए कहा कि मुझे इस बात का अफसोस है कि जिन लोगों को मैंने जीवन में सहारा दिया, वे अब गद्दार के साथ मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा विरोधी दल देशव्यापी कार्ययोजना पर निर्णय लेने के लिए दिल्ली में बैठक करेंगे। धरने वाली जगह पर उसने नारे लगाए, मैं लड़ूंगी या मर जाऊंगी। हालांकि, पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि निजी स्वार्थों के लिए पार्टी से नेताओं के अलग होने से संगठन के पुनर्निर्माण में मदद मिलेगी और टीएमसी इस संकट से और भी मजबूत होकर उभरेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि लोग क्यों डरे हुए हैं? लोग क्यों चिंतित हैं? पूरा माहौल ही बदल गया है। कोलकाता और बंगाल को गुंडों के हवाले कर दिया गया है। टीएमसी टिकट पर विधानसभा सीटें जीतने वाले अधिकांश नए चेहरे अनुपस्थित थे, वहीं बनर्जी के साथ पार्टी के पुराने नेता फिरहाद हकीम, मदन मित्रा, डेरेक ओब्रायन, कल्याण बनर्जी और डोला सेन नजर आए। हालांकि, पार्टी प्रमुख ने जोर देकर कहा कि उनके भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर शनिवार को हुए हमले, चुनाव के बाद कथित हिंसा और फेरीवालों को बेदखल करने के विरोध में धरना निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शाम तक जारी रहेगा।

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का राष्ट्रविरोधी ताकतों पर तीखा हमला, बोले- लोकतंत्र का दुरुपयोग बंद हो

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को किसी का नाम लिए बिना, राष्ट्रविरोधी तत्वों का समर्थन करने वाले व्यक्तियों पर तीखा हमला बोला और कहा कि लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग भारत की संप्रभुता और स्थिरता को कमजोर करने वाली ताकतों का बचाव करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। एक्स पर एक पोस्ट में, रिजिजू ने कहा कि उन्हें भारत पर गर्व है, लेकिन उन लोगों की वे कड़ी आलोचना करते हैं जो कथित तौर पर राष्ट्रीय हितों से ऊपर अपने निजी हितों को प्राथमिकता देते हैं। रिजिजू ने लिखा कि मुझे भारत में रहने पर बहुत गर्व है, लेकिन मुझे उन स्वार्थी लोगों पर शर्म आती है जिनका कोई नैतिक मूल्य नहीं है, जो केवल धन के पीछे भागते हैं और आतंकवादियों, माओवादियों और भारत विरोधी गिरोहों और अपराधियों का बचाव करते हैं! लोकतांत्रिक मूल्यों के महत्व पर जोर देते हुए, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत खुली बहस और असहमति के लिए प्रतिबद्ध है, बशर्ते कि ऐसी स्वतंत्रता का दुरुपयोग राष्ट्र के हितों के खिलाफ काम करने वाले तत्वों का समर्थन करने के लिए न किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि हमारे

भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती खुली बहस और सेंसरशिप के डर के बिना असहमति व्यक्त करने का अधिकार है। एकमात्र शर्त यह है कि उन तत्वों का समर्थन न करें जो भारत की अटूट संप्रभुता, आंतरिक स्थिरता और आर्थिक विकास को नुकसान पहुंचाने और कमजोर करने की सक्रिय रूप से कोशिश कर रहे हैं।

बीजेपी को पेपर लीक से नहीं, चर्चा से दिक्कत...अरविंद केजरीवाल का सरकार पर बड़ा हमला

नई दिल्ली।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भाजपा सरकार पर तब हमला बोला जब उनके पार्टी नेता ने आरोप लगाया कि प्रयागराज में उत्तर प्रदेश पुलिस और सरकारी अधिकारियों ने छात्रों के साथ पेपर लीक मामले पर उनकी चर्चा को बाधित किया। संजय सिंह की पोस्ट को साझा करते हुए केजरीवाल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह पेपर लीक जैसी समस्याओं को सुलझाने में कोई कार्रवाई नहीं करती, बल्कि इस पर चर्चा को रोकने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा को पेपर लीक से कोई समस्या नहीं है। समस्या पेपर लीक पर हो रही चर्चा से है। यह घटना संजय सिंह द्वारा सोमवार को लगाए गए आरोपों के बाद सामने आई है। संजय सिंह ने आरोप लगाया था कि प्रयागराज में उत्तर प्रदेश पुलिस और सरकारी अधिकारियों ने पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों से उनकी बातचीत को रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा था कि तानाशाही चरम पर पहुंच गई है। इ्र पर वीडियो साझा करते हुए संजय सिंह ने कहा कि प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में तानाशाही चरम पर पहुंच गई है। बंद कमरों में भी लाखों छात्रों के

भविष्य पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दी जा रही है; प्रशासन पेपर लीक की बात को भी रोकने के लिए आ गया है।

मोदी-योगी की दो इंजन वाली सरकार पूरी तरह विफल हो गई है और विपक्ष को कुचलना चाहती है। वीडियो में संजय सिंह ने व्यवधान को लेकर अधिकारियों से सवाल किया कि क्या देश के लाखों छात्रों को प्रभावित करने वाले पेपर लीक के बारे में बात करना अवैध हो गया है? उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सार्वजनिक स्थान के लिए अनुमति आवश्यक है। हम कॉन्फ्रेंस रूम में चर्चा कर रहे हैं। क्या हम देश के खिलाफ कोई बात कर रहे हैं? हम उन पेपर लीक पर चर्चा कर रहे हैं जिनके जरिए आपको भी यह पद मिला है। आपके बच्चे भी इन लीक से प्रभावित हैं। क्या लोकतंत्र में इनके बारे में बात करना अवैध है? मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूं। यह घटनाक्रम हाइस्कूल-त 2026 को लेकर चल रहे विवाद के बीच सामने आया है, जिसे पेपर लीक और प्रशासनिक खामियों के आरोपों के बाद 21 जून के लिए पुनर्निर्धारित किया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अपनी जांच जारी रखे हुए है और कई गिरफ्तारियां कर चुकी है, जबकि देश के कई हिस्सों में छात्र समूहों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है।

यह जवाबदेही नहीं, कवर-अप है - सीबीएसई चेयरमैन-सचिव के तबादले पर राहुल का हमला, बोले- असली जिम्मेदार बचाए गए

एजुकेशन डेस्क। सीबीएसई चेयरमैन और सचिव के ट्रांसफर तथा ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति गठित किए जाने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने इस कार्रवाई को कवर-अप बताते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाने और स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग की है।

क्या बोले राहुल गांधी?

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा-

सीबीएसई अध्यक्ष - ट्रांसफर।

सीबीएसई सचिव - ट्रांसफर।

एक-सदस्यीय जांच समिति गठित।

असली जिम्मेदार, धर्मेंद्र प्रधान - सुरक्षित।

उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों को हटाकर मंत्री को बचाया गया है। राहुल गांधी ने कहा, यह जवाबदेही नहीं, यह कवर-अप है।

शिक्षा मंत्री को हटाने की मांग

कांग्रेस नेता ने अपनी पोस्ट में कहा कि उनकी मांग पहले की तरह अब भी कायम है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त किया जाए और पूरे मामले की स्वतंत्र न्यायिक जांच कराई जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार की एक महीने पुरानी अधूरी फाइल को चुपचाप बंद करने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 18.5 लाख सीबीएसई छात्रों की परवाह होती तो शिक्षा मंत्री को पहले ही हटा दिया गया होता।।

ओएसएम सिस्टम को लेकर बढ़ा विवाद

दरअसल, हाल ही में केंद्र सरकार ने सीबीएसई के ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम से जुड़ी सेवाओं की खरीद प्रक्रिया की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति बनाई है।

जम्मू के किश्तवाड़ में 2 जगह बादल फटा- लैंडस्लाइड से सड़कें बंद, सुरक्षाबल रेस्क्यू में जुटे

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में मंगलवार को दो जगह बादल फटे हैं। पहला बादल सरथल के गहन इलाके में और दूसरा माछीपाल क्षेत्र में फटा है। कुछ इलाकों में लैंडस्लाइड से सड़कें बंद हो गई हैं। अधिकारियों के मुताबिक, फिलहाल किसी जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है। पुलिस, रेड क्रॉस, राजस्व विभाग और अन्य एजेंसियों की टीमें मौके पर भेजी गई हैं। सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि स्थानीय लोगों से लगातार संपर्क किया जा रहा है, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। इधर, राजस्थान और मध्य प्रदेश में आंधी-बारिश से 5 लोगों की मौत हो गई। एमपी के नीमच में सोमवार रात मकान की छत ढहने से मां-बेटे की मौत हो गई। वहीं, राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर में दीवार ढहने से दो बच्चों सहित 3 लोगों की जान चली गई। बादल फटना ऐसी स्थिति है, जब किसी छोटे इलाके में बहुत कम समय के भीतर अचानक बेहद तेज बारिश होने लगती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, यदि एक घंटे में 100 मिमी या उससे ज्यादा बारिश हो जाए, तो उसे क्लाउडबर्स्ट माना जाता है। यह घटना आमतौर पर 10 से 20 वर्ग किलोमीटर के छोटे क्षेत्र में होती है और पहाड़ी इलाकों में ज्यादा देखने को मिलती है।

बादल फटने से अचानक बाढ़, भूस्खलन और सड़कों के क्षतिग्रस्त होने का खतरा बढ़ जाता है।

खान सर के कोचिंग सेंटर पर ताबड़तोड़ फायरिंग! कुछ लोगों को गरीबों के पढ़ने से दिक्कत- खान सर

पटना। पटना के मुसल्लहपुर थाना क्षेत्र स्थित चर्चित शिक्षक खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर फायरिंग की घटना सामने आई है. जानकारी के मुताबिक, करीब 5 से 6 राउंड गोलियां चलाई गईं, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है. पुलिस अब हमलावरों की पहचान के लिए क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने की तैयारी में जुटी है. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल फैल गया. सूचना मिलते ही मुसल्लहपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, साथ ही फुटपाथी दुकानदारों और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर रही है. थाना अध्यक्ष ने कहा है कि गोली चलने की घटना की पुष्टि की जा रही है. फिलहाल फायरिंग के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है और पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच में जुटी है. खान सर ने बताया कि क्लास खत्म हो चुकी थी और हाल ही में बिहार पुलिस का रिजल्ट आने के कारण बड़ी संख्या में छात्र सफल हुए थे. इसी वजह से संस्थान में हजारों छात्रों को सम्मानित किया गया, जिससे सभी लोग काफी थके हुए थे. इसी दौरान कुछ असामाजिक तत्व वहां पहुंचे और कोचिंग को दो दिन के भीतर उठा देने की धमकी देने लगे. उन्होंने गार्ड पर भी हमला किया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया और फिलहाल अस्पताल में भर्ती है. खान सर ने आगे कहा कि यह हमला करने वाले असामाजिक तत्व ही हैं, जिन्होंने मौके पर मौजूद लोगों को भी धमकाया. उनका कहना है कि कुछ लोगों को यह आपत्ति है कि इतनी कम फीस में बड़ी संख्या में छात्रों को पढ़ाया जा रहा है और अच्छे रिजल्ट दिए जा रहे हैं. उन्होंने प्रशासन से मांग की कि कोचिंग संस्थान की सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि गरीब और साधारण परिवार के छात्रों को भी शिक्षा पाने का पूरा अधिकार है. खान सर का कहना है कि जब बड़ी संख्या में छात्र सफल होते हैं, तो ऐसे असामाजिक तत्व इस उपलब्धि को दबाने की कोशिश करते हैं. गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब खान सर के संस्थान के आसपास किसी आपराधिक घटना की चर्चा हुई हो. इससे पहले 10 मई 2019 को उनके कोचिंग सेंटर को निशाना बनाकर देसी बम से हमला किया गया था. उस समय सुबह करीब 10 बजे कदमकुआं थाना क्षेत्र के मुसल्लहपुर हाट स्थित खान जीएस रिसर्च सेंटर के बाहर अज्ञात बदमाशों ने लगातार दो देसी बम फेंके थे. उस हमले में कोचिंग संस्थान के कार्यालय के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा था, जबकि बाहर खड़ी एक छात्र की स्कूटी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी. हालांकि उस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं थी. खान सर ने विभिन्न मंचों पर यह दावा किया था कि बेहद कम फीस में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के कारण कुछ स्थानीय कोचिंग माफिया और असामाजिक तत्व उनसे नाराज थे और उनके संस्थान को बंद कराने की कोशिश कर रहे थे. बता दें कि खान सर बिहार की राजधानी पटना के बेहद लोकप्रिय शिक्षक और यूट्यूबर हैं. अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म खान जीएस रिसर्च सेंटर के माध्यम से वे देशभर के लाखों छात्रों को कम लागत में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए जाने जाते हैं. फिलहाल ताजा फायरिंग की घटना को लेकर पुलिस जांच जारी है.